



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2015/वैशाख 15, 1937

No. 146 ]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2015/VAISAKHA 15, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 1 मई, 2015

सं. टीएमपी/13/2009-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/13/2009-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम:

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)  
(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2015 के 28वें दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

2. वीपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएमपी/13/2009-वीपीटी दिनांक 18 फरवरी, 2011, जिसे 31 मार्च, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित की थी। यह प्राधिकरण वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता कई बार विस्तारित कर चुका है; पिछला विस्तार आदेश दिनांक 2 जनवरी, 2015 द्वारा 31 मार्च, 2015 तक था।

3.1 वीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 मार्च, 2013 के साथ अपने पत्रों दिनांक 8 फरवरी, 2013 द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई 20 सितम्बर, 2013 को आयोजित की गई थी। हमारे पत्र दिनांक 8 अगस्त, 2013 द्वारा वीपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पत्तन द्वारा 19 नवम्बर, 2013 को प्रेषित की गई थी।

3.2 वीपीटी ने अपने पत्रों दिनांक 14 अगस्त, 2014, 2 सितम्बर, 2014 और 3 सितम्बर, 2014 द्वारा, बाद में अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया था। वीपीटी के संशोधित प्रस्ताव पर भी संबद्ध उपयोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

3.3 तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने दूसरे पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा केपिटल निकर्षण की लागत वसूल करने के लिए लेवी शुरू करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और अपने दरमानों में शामिल करने का अनुरोध किया था। उक्त प्रस्ताव भी उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था।

4.1 इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं. 8(1)/2014-टीएमपी दिनांक 13 जनवरी, 2015 द्वारा "महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015" जारी की गई थी जिसे इस प्राधिकरण द्वारा राजपत्र सं. 30 दिनांक 27 जनवरी, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। नई "महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015" 13 जनवरी, 2015 से लागू हुई है।

4.2 एमओएस द्वारा महापत्तन न्यासों के लिए 2015 की नई प्रशुल्क नीति में परिकल्पित प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रशुल्क निर्धारण पद्धति से काफी भिन्न है। इसलिए, वीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर 2005 दिशानिर्देशों के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकी थी। इसके मददेनजर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 13 फरवरी, 2015 द्वारा वीपीटी के दरमानों के सामान्य संशोधन हेतु वीपीटी का प्रस्ताव बन्द कर दिया था। वीपीटी को एमओएस द्वारा घोषित 2015 की नई प्रशुल्क नीति के अनुसार संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी गई है।

5. प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 1.5 के अनुसार, इस प्राधिकरण ने मसौदा कार्यकरण दिशानिर्देश तैयार किए थे और सभी महापत्तन न्यासों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। प्रशुल्क नीति, 2015 को कार्यान्वित करने के लिए मसौदा कार्यकरण दिशानिर्देश सभी महापत्तन न्यासों से विचार-विमर्श कर तैयार किए जाने हैं। इसके अलावा, वीपीटी को अभी नई प्रशुल्क नीति, 2015 का अनुसरण करते हुए अपना प्रस्ताव दाखिल करना है। जब वीपीटी से प्रस्ताव प्राप्त होगा उसपर नई प्रशुल्क नीति, 2015 का अनुसरण करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

6.1 चूंकि, वीपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा बताया है कि कार्यकरण दिशानिर्देशों की अधिसूचना अभी लंबित है और उसे संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने में समय लगेगा। इसके मददेनजर, वीपीटी ने मौजूदा दरमान की वैधता एमओएस द्वारा घोषित नई प्रशुल्क नीति, 2015 के अनुसार संशोधित दरमान, जब इस प्राधिकरण द्वारा भेजा और अनुमोदित किया जाएगा, के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है।

6.2 वीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के मददेनजर, यह प्राधिकरण वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से 30 सितम्बर, 2015 अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है।

6.3 1 अप्रैल, 2013 के बाद की अवधि के लिए वीपीटी को प्रोद्भूत होने वाले अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, का संव्यवहार महापत्तन न्यासों हेतु नई प्रशुल्क नीति, 2015 द्वारा शासित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/असा./143/2015 (34)]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 1st May, 2015

**No. TAMP/13/2009-VPT.**— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/13/2009-VPT

The Visakhapatnam Port Trust

-----

Applicant

### QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 28<sup>th</sup> day of April, 2015)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the VPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/13/2009-VPT dated 18 February, 2011 which was notified in the Gazette of India on 31 March, 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of existing SOR of VPT on couple of occasions; the last extension being till 31 March, 2015 vide Order dated 2 January, 2015.

3.1 The proposal filed by the VPT vide its letters dated 8 February, 2013 along with its letter dated 22 March, 2013 under the tariff guidelines of 2005 was taken on consultation with the concerned users / user associations. Joint hearing on the proposal was held on 20 September, 2013. The additional information / clarification sought from the VPT vide our letter dated 8 August, 2013 had been furnished by the port on 19 November 2013.

3.2 The VPT, vide its letters dated 14 August, 2014, 2 September, 2014 and 3 September, 2014, had subsequently filed its revised proposal. The revised proposal of the VPT was also taken on consultation with concerned users.

3.3 Subsequently, the VPT vide its another letter dated 10 December, 2014 had submitted a proposal for introduction of a levy to recover the cost of Capital Dredging and had requested for inclusion in its Scale of Rates. The said proposal also had been circulated to the users / user organisations seeking their comments.

4.1 In the meantime, the Ministry of Shipping (MOS), vide its letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January, 2015 issued the new “Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015” which was notified in the Gazette of India vide Gazette No. 30 dated 27 January, 2015 by this Authority. The new “Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015” has come into effect from 13 January, 2015.

4.2 The tariff fixation process envisaged in the new Tariff Policy of 2015 for Major Port Trust by MOS, is significantly different from the tariff fixation method stipulated in the Tariff Guidelines of 2005. Hence, the proposal filed by VPT could not be processed under 2005 guidelines. In view of this, this Authority vide its Order dated 13 February, 2015 had closed the VPT proposal for general revision of its Scale of Rates. The VPT has been advised to file a revised proposal in accordance with the new Tariff policy of 2015 announced by the MOS.

5. As per Clause 1.5 of Tariff Policy, 2015, this Authority has formulated draft working guidelines and circulated to all Major Port Trusts for their comments. The draft working guidelines to operationalise the Tariff Policy, 2015 is to be firmed up in consultation with all Major Port Trusts. Further, the VPT is yet to file its proposal following new Tariff Policy, 2015. The proposal when received from the VPT will have to be processed following the new Tariff Policy, 2015.

6.1 Since, the extended validity of the existing SOR of VPT, has expired on 31 March, 2015, the VPT vide its letter dated 30 March, 2015 has stated that notification of working guidelines is pending and it may take time for submission of revised proposal. In view of this, the VPT has requested to extend the validity of the existing SOR till the effective date of implementation of the revised SOR in accordance with the new Tariff Policy, 2015 announced by MOS when sent and approved by this Authority.

6.2 In view of the request made by the VPT, this Authority extends the validity of the existing SOR of VPT from the date of its expiry till 30 September, 2015 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6.3 The treatment of additional surplus, if any, accruing to the VPT for the period beyond 1 April, 2013 will be governed by the new Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2015/(34)]